E-ISSN: 2664-603X
P-ISSN: 2664-6021
IJPSG 2024; 6(1): 323-327
www.journalofpoliticalscience.com
Received: 13-02-2024
Accepted: 16-03-2024

नीरज कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर पी.जी.राजनीति विज्ञान विभाग जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, बिहार, भारत

CorrespondingAuthor:
नीरज कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर पी.जी.राजनीति विज्ञान विभाग जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, बिहार, भारत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत–चीन संबंध : एक मूल्यांकन

नीरज कुमार

DOI: https://doi.org/10.33545/26646021.2024.v6.i1e.340

सारांश
नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के संकेत दिए। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के आरंभ से अब तक भारत चीन के बीच औपचारिक वार्ताएं और सीमा पर टकराव दोनों हुए हैं। डोकलाम तथा गलवान में टकराव इसके उदाहरण है। अनुच्छेद 370 पर चीन ने अपना नकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त किया अर्थात चीन सीमा से लेकर आंतरिक मामले में उलझने में सक्रिय दिखा। सकारात्मक पहल के बाद चीन की तरफ से कुछ ऐसा कार्य किया जाता है या वक्तव्य आता है तब यह प्रतीत होने लगता है कि चीन एक तरफा अपने हित को ध्यान में रखकर ही भारत से संबंध निभाना चाहता है। इन स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रकार की रणनीति को अपनाया है।इसका मूल्यांकन करने का प्रयास इस शोध पत्र में किया गया है। इस शोध पत्र को द्वितीयक स्रोत के आधार पर लिखा गया है।

शब्द कुंजी – डोकलाम, वुहान स्पिरिट, चेन्नई कनेक्ट, जी–20।

प्रस्तावना
भारत और चीन एशिया के दो बड़े शक्तियां हैं। दोनों के आपसी संबंध पूरे क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। आजादी के बाद से दोनों देशों की स्थितियां तथा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में काफी बदलाव हुआ है। वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय विकास के लिए अच्छी कूटनीति की आवश्यकता होती है। हर राष्ट्र इस तत्व को स्वीकार करता है तथा इस पर अमल करने का प्रयास करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण के समय से ही विदेशी मामलों या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रति काफी सचेत दिखे। उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में अपने पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नए उत्साह का परिचय पूरी दुनिया को दिया। वर्ष 2013 में चीन के प्रधानमंत्री ली केकीयंग की भारत यात्रा के समय पंचशील की 60वीं वर्षगांठ को मैत्रीपूर्ण आदान–प्रदान का वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। इस संदर्भ में भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने चीन की यात्रा की। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने दोनों देशों के बीच हर क्षेत्र में अच्छे संबंध की वकालत की। उनके अनुसार भारत और चीन प्राचीन सभ्यताएं हैं। हम पड़ोसी हैं। हम रणनीतिक साझेदार हैं। ऐतिहासिक रूप से, ऐसा बहुत कुछ रहा है जिसने हमें एक साथ बांधा है, न केवल समान और वस्तुओं के आधार प्रदान के माध्यम से बल्कि विचारों, मूल्य और दर्शन के समृद्ध आदान–प्रदान के माध्यम से। 21वीं सदी की अनिवार्यताएं हमें एक दूसरे के उद्देश्यों की बेहतर समझ और पारस्परिक लाभ के लिए अधिक उद्देश्य पूर्ण सहयोग की ओर प्रेरित करती हैं। हमारे दोनों देशों के लोगों के बीच सभी क्षेत्रों में बेहतर संपर्क मजबूत समग्र द्विपक्षीय संबंध के लिए आवश्यक शर्त है[1]। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि वह चीन के बहुत शीघ्र एक विकसित देश बन जाने की आशा करते हैं[2]। लेकिन यह विरोधाभासी रहा की एक तरफ जहां हामिद अंसारी चीन में पंचशील समझौते की 60 वीं वर्षगांठ मनाने चीन के दौरे पर हैं और चीन अरुणाचल प्रदेश के हिस्से पर अपना दावा कर रहा था। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद चीन ने अपने विदेश मंत्री वांग को विशेष दूत के रूप में जून 2014 में भारत भेजा। उन्होंने भारत यात्रा के दौरान कहा कि दोनों देशों के बीच मतभेद से अधिक सहमति है[3]। वांग ने सीमा विवाद आतंकवाद साउथ चीन समुद्र संबंधित मुद्दे पर चर्चा की उन्होंने मोदी को चीन का पुराना मित्र बताया और कहा कि उनके चुनाव ने प्राचीन सभ्यता में नई शक्ति का संचार किया[4]। चीन सरकार ने भी इस यात्रा के संदर्भ में सकारात्मक विचार व्यक्त किया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनविंग ने कहा कि इस यात्रा से पता चलता है कि भारत चीन भारत संबंध अब नए युग में है।... हम प्रतिद्वंद्वी के बजाय स्वाभाविक भागीदार है तथा चीनी और भारतीय सपने एक दूसरे के साथ

एकीकृत होते हैं, इसलिए हमें एक दूसरे के साथ घनिष्ठ विकास साझेदारी बनानी चाहिए"[5]। परंतु चीन सरकार के स्वभाव तथा बयान इस समय थोड़ा आशा के विपरीत लग रहे थे। क्योंकि पिछली सरकार के समय लगभग 14 महीने पहले चीनी सैनिक भारत प्रशासित कश्मीर में प्रवेश किए थे। जिससे दोनों देशों के मध्य तनाव की स्थिति हो गई थी। अंकित पांडा के अनुसार बीजिंग के लिए यह काफी अजीब लगता है कि उसने राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के साथ संबंधों में बदलाव का रास्ता चुना है[6]। चीन के विदेश मंत्री ने इस यात्रा को मित्रों को जानने की यात्रा कहा। उन्होंने इसे हमारी मौजूदा दोस्ती को मजबूत करने वाली यात्रा भी कहा। द हिंदू को दिए गए साक्षात्कार में वांग ने भारत चीन संबंधों के बारे में बहुत सकारात्मक तथा ऊर्जावान विचार प्रकट किया। जो इस प्रकार हैं "चीन –भारत संबंध 21वीं सदी में सबसे गतिशील और अत्यधिक संभावित द्विपक्षीय संबंध है। मल्टीपोलर दुनिया की प्रक्रिया में दो प्रमुख ताकतों चीन और भारत के लिए शांतिपूर्ण, सहयोगात्मक और समावेशी विकास हासिल करना महत्वपूर्ण है। इससे न केवल हमारे दोनों देशों के लोगों को भारी लाभ होगा बल्कि एशिया और दुनिया में शांति और मानव जाति के विकास के मुद्दे को हल करने में योगदान देगा।... यह अपरिहार्य है कि पड़ोसियों के बीच, इतिहास से छूटे कुछ मुद्दों या तत्काल के हितों में कुछ मतभेद हो सकते हैं। हालांकि, मुझे जोर देना चाहिए कि चीन और भारत के बीच मतभेदों से कहीं अधिक रणनीतिक सहमति है और सहयोग हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कोई भी देश अपना पड़ोसी नहीं चुन सकता, परंतु दोस्ती को बढ़ावा मिल सकता है। कुछ मुद्दों को टाला नहीं जा सकता, लेकिन नए उत्तर अवश्य ढूंढे जा सकते हैं। कोई इतिहास दोबारा नहीं लिख सकता, लेकिन भविष्य हमारे हाथ में है[7]।

जुलाई 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिन की मुलाकात ब्राजील के फोर्टलेजा में हुई। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और चीन के पास न केवल पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी बनाने के लिए बल्कि एशिया और वैश्विक समृद्धि के उत्प्रेरक एजेंट के रूप में भी काम करने के लिए प्रचुर अवसर हैं।राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को रेखांकित किया और कहा "जब भारत और चीन मिलते हैं तो पूरी दुनिया देखती है"[8]। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आपसी विश्वास को मजबूत करने और सीमा पर शांति बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया।उन्होंने कहा कि यदि भारत और चीन सीमा प्रश्न को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल कर सकते हैं, तो यह शांतिपूर्ण संघर्ष समाधान पर पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण स्थापित करेगा[9]।

चीन के राष्ट्रपति का भारत दौरा

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दोनों देशों के द्विपक्षी संबंध को बेहतर करने के लिए भारत की यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि "मैं यह कहना चाहूंगा कि भारत और चीन संबंधों के लिए यह विशाल संभावनाओं से भरा एक ऐतिहासिक अवसर है। हम अपने संबंधों में एक नए युग की शुरुआत कर सकते हैं। यदि हम अपने अवसरों और चुनौतियों के प्रति संबंधी संवेदनशील हैं, तो मुझे विश्वास है कि हम इसे बड़ी सफलता बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे"[10]। प्रधानमंत्री मोदी पत्रकारों से वार्ता करते समय काफी आशावान दिखे। उन्होंने कहा कि भारत और चीन संबंध इंच (भारत और चीन) से मील (मिलेनियम ऑफ एक्सेप्शनल सिनर्जी) की ओर बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा "प्रत्येक इंच चलने पर हम मानवता का इतिहास फिर से लिख सकते हैं तथा प्रत्येक मील दर मील बढ़ने पर यह ग्रह बेहतर स्थान बन सकता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत और चीन मिलकर कई मील का रास्ता पार कर सकते हैं। कई मील साथ चलने पर दो देश आगे ही नहीं बढ़ते बल्कि समस्त एशिया तथा मानवता प्रगति तथा समन्वय की ओर अग्रसर होती है"[11]। भारत और चीन के भावी संबंधों के बारे में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में प्रधानमंत्री ने बताया कि हमारे संबंध महज अंक गणित से काफी दूर तक के हैं। उनके बीच अनूठी केमिस्ट्री है जो निर्धारण क्षण बना सकते हैं[12]। इस यात्रा के दौरान कई समझौते भी दोनों देशों के मध्य हुए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन दौरा

चीन के राज्य परिषद के प्रधान ली केकियांग के निमंत्रण पर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन गए। दोनों पक्ष के नेताओं ने कहा कि भारत और चीन के लिए अपने द्विपक्षीय संबंधों को समृद्ध करना एक ऐतिहासिक अनिवार्यता है [13]। एशियाई सदी के सपने को साकार करने के लिए दोनों देशों का आगे बढ़ना जरूरी है। इस पर दोनों देशों के नेताओं में सहमति दिखाई दी। उन्होंने कहा कि भारत चीन द्विपक्षीय संबंध 21वीं सदी में एशिया और वास्तव में वैश्विक स्तर पर एक निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं [14]। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए की दोनों देश एक दूसरे के हितों के प्रति संवेदनशील होंगे। यह सहमति इसलिए जरूरी थी क्योंकि चीन प्रायः अपने हित तक ही सोचता है तथा इससे बहुत से मामलों में तनाव होता है। दोनों देशों के बीच अधिक सांस्कृतिक, पर्यटन, आर्थिक और लोगों के जुड़ाव को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने के लिए, एक दूसरे के देश में एक अतिरिक्त महावाणिज्य दूतावास स्थापित किया जाएगा। भारत चेंगदू में एक नया महावाणिज्य दूतावास खोलेगा, जबकि चीन चेन्नई में एक नया महावाणिज्य दूतावास खोलेगा[15]। घनिष्ठ संवाद और आपसी समझ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दोनों पक्षों ने 'भारत चीन थिंक टैंक फोरम' स्थापित करने का निर्णय लिया, जो भारत और चीन में बारी–बारी से सालाना बैठक करेगा[16]। आतंकवाद के सभी रूपों की आलोचना की गई। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु था। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार तथा भारत को अधिक जिम्मेदारी देने के बाद कही गई। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्यता के आवेदन का चीन ने स्वागत किया। 2017 में भारत शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य बना तथा 2023 में दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन भी हुआ।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की चीन यात्रा

आधिकारिक घोषणा के अनुसार, इस यात्रा का उद्देश्य राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक और लोगों से लोगों (पीपल टू पीपल) के क्षेत्र के साथ–साथ महत्व के क्षेत्र और वैश्विक मुद्दों को कवर करने वाले द्विपक्षीय मुद्दों की एक पूरी श्रृंखला पर चर्चा करना था[17]। राष्ट्रपति ने यात्रा के साथ–साथ चीनी नेताओं के साथ चर्चा को "सार्थक और उत्पादक" बताया[18]। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों के अनेक मुद्दों पर बात हुई। आर्थिक, सांस्कृतिक और सीमा विवाद जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर राष्ट्रपति ने अपने विचार रखे। राष्ट्रपति ने "मेक इन इंडिया" कार्यक्रम में चीन को निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। भारत के राष्ट्रपति ने आतंकवाद के सभी प्रकारों की आलोचना की तथा कहा कि उसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं है, ना ही आतंकवाद किसी विचारधारा से जुड़ा हुआ है। पेकिंग विश्वविद्यालय में भारतीय राष्ट्रपति ने सीमा विवाद पर कहा कि "दोनों तरफ के लोगों को इस उद्देश्य को निश्चित करते हुए कार्य करना चाहिए कि हम अपने आने वाली पीढियां के ऊपर अनसुलझे मुद्दों तथा मतभेद का भार न डालें" [19]। दोनों पक्ष सीमा विवाद को सुलझाने को सहमत हैं। प्रणब मुखर्जी ने इस बात पर जोर दिया कि आम नागरिकों को भारत चीन संबंधों के केंद्र में रखना चाहिए। पेकिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने कहा "हमारे संबंधों में गुणात्मक परिवर्तन

के लिए लोगों को केंद्र में रखना आवश्यक है[20]"। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि "भारत और चीन के बीच राजनीतिक समझ घनिष्ठ विकासात्मक साझेदारी के लिए महत्वपूर्ण है, जिसे उन्नत राजनीतिक संचार के माध्यम से हासिल किया जा सकता है"[21]। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की चीन यात्रा दो दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रही है – (1) जहां तक द्विपक्षीय संबंधों में मौजूद चुनौतियों का सवाल है, यह एक अनुकूल माहौल और सर्वसम्मति बनाने वाली यात्रा थी। (2) इसने दोनों देशों में समर्थन के क्षेत्र को विस्तृत कर संबंधों को व्यापक आधार देने का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया[22]।

डोकलाम विवाद

डोकलाम भारत, चीन और भूटान के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। यह क्षेत्र चीन तथा भूटान के मध्य एक विवादित क्षेत्र है। जिस पर दोनों देश अपना दावा करते हैं। डोकलाम में चीन सड़क का निर्माण कर रहा था। भूटान के कहने पर भारत ने इस मुद्दे पर हस्तक्षेप किया। यह मुद्दा तथा क्षेत्र भारत के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण और संवेदनशील था। यह क्षेत्र सिलीगुड़ी से कुछ ही दूरी पर है। भारत– चीन के सैनिक एक दूसरे के सामने 72 दिनों तक आमने–सामने डटे रहे। यह चीन की विस्तारवादी नीति का परिणाम था। अपनी परिधि के आसपास पी.आर. सी. की मुखरता उसकी सदियों पुरानी धारणा के कारण है कि दबे हुए पड़ोस' को स्थिरता के लिए एक आवश्यक शर्त माना जाता है। अपनी पुस्तक 'ऑन चाइना' में हेनरी किसिंजर ने बताया है कि पी. आर. सी. खुद को एक लौटती हुई शक्ति मानता है और प्रभाव डालने को अप्राकृतिक नहीं मानता है[23]। इस विवाद के चलते ही हर वर्ष होने वाली बॉर्डर पर्सनल मीटिंग उस वर्ष नहीं हुई। हर वर्ष एक अक्टूबर को यह मीटिंग भारत और चीन के बीच होती थी।

वुहान में भारत –चीन प्रथम अनौपचारिक शिखर सम्मेलन

शिखर सम्मेलन का उद्देश्य "द्विपक्षीय और वैश्विक महत्व के व्यापक मुद्दों पर विचारों का आदान–प्रदान करना और वर्तमान और भविष्य की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के संदर्भ में राष्ट्रीय विकास के लिए अपने संबंधित दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को विस्तृत करना था"[24]। प्रधानमंत्री मोदी ने... रेखांकित किया कि दो प्रमुख देशों के रूप में भारत और चीन के क्षेत्रीय और वैश्विक हित व्यापक और परस्पर जुड़े हुए हैं[25]। विदेश मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति में भारत और चीन को रणनीतिक और निर्णयात्मक स्वायत्तता वाली दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और प्रमुख शक्तियां कहा गया है और कहा गया है कि "वर्तमान वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत और चीन के बीच शांतिपूर्ण, स्थिर और संतुलित संबंध स्थिरता के लिए एक सकारात्मक कारक होंगे"[26]। शी जिनपिंग ने दोनों पक्षों से "21वीं सदी में स्थिरता, विकास और समृद्धि वाला एशिया बनाने" का आह्वाहन किया[27]। डोकलाम विवाद के बाद दोनों देशों के प्रमुखों की यह प्रत्यक्ष पहली मीटिंग थी। इस विवाद का प्रभाव जी–20 सम्मेलन में दिखा था। पर उपरोक्त बयान व विचार से यही प्रतीत होता है कि दोनों देश अच्छे वह दीर्घकालिक संबंध चाहते हैं। भारत– चीन सीमा प्रश्न पर विशेष प्रतिनिधियों के काम के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया और उनसे निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान के लिए अपने प्रयासों को तेज करने का आग्रह किया[28]। शी जिनपिंग ने मतभेदों को अधिक परिपक्व तरीके से निपटाने की आवश्यकता व्यक्त की और पीएम मोदी ने दोनों पक्षों को मतभेदों को ठीक से संभालने और नियंत्रित करने का आग्रह किया[29]। सीमा के प्रश्न पर शी तथा चीन सरकार के विचार कितने भी अच्छे प्रतीत होते हो परंतु गलवान घाटी वाले मामले में चीन ने नकारात्मक रुख ही दिखाया। वह सीमा विवाद पर एकपक्षीय सोचता है। वह शांतिपूर्ण वातावरण बनने नहीं देता है। दोनों पक्ष शिखर सम्मेलन के दौरान सांस्कृतिक और लोगों से लोगों (पीपल टू पीपल) के आदान–प्रदान को मजबूत करने की सुविधा के लिए नए तंत्र स्थापित करने पर सहमत हुए। भारत ने आतंकवाद की आलोचना की तथा भारत यह चाहता है कि चीन इस संदर्भ में सक्रिय दिखे। पर चीन ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसका कारण यह हो सकता है, चीन इस समस्या से अभी दूर है। दोनों देशों ने समानता आधारित विश्व आर्थिक व्यवस्था का समर्थन किया। दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अधिक लोकतांत्रिक बनाने, विकासशील देशों और उभरते बाजारों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने, बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था का समर्थन करने, संरक्षणवाद का विरोध करने और खुले, समावेशी, संतुलित और सभी को लाभ पहुंचाने वाले आर्थिक वैश्वीकरण के लिए मिलकर काम करेंगे[30]। भारत –चीन दोनों ही देश भविष्य में भी अनौपचारिक शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमत हुए। भारत के प्रधानमंत्री ने अगला सम्मेलन भारत में होने की ओर संकेत भी दिया। अनौपचारिक शिखर सम्मेलन भारत और चीन के बीच उच्चतम स्तर पर राजनीतिक जुड़ाव के मॉडल का प्रतीक है। निश्चित रूप से, इससे आपसी हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर राजनीतिक, रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संवाद तेज हो गए दोनों पक्षों ने सहयोग के महत्वपूर्ण क्षेत्र के साथ–साथ विचारों पर भी प्रकाश डाला है। आधिकारिक बयानों के विश्लेषण से विभिन्न मुद्दों पर समानता और कुछ मुद्दों पर मतभेद पता चलता है। राजनीतिक और दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य के लिए आपसी हित के सभी मुद्दों पर और बहस और आम समिति बनाने की आवश्यकता है। फिर भी, अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के दौरान विभिन्न मुद्दों पर बनी व्यापक सहमति दोनों नेताओं के दूरदर्शी दृष्टिकोण का संकेत देती है[31]। वुहान सम्मेलन के 8 महीने बाद किंगदाओ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई। दोनों देशों के नेताओं ने वुहान भावना को अभिव्यक्त किया तथा उसके अनुसार कार्य करने को भी सहमत हुए। अनौपचारिक शिखर सम्मेलन ने भारत और चीन के बीच उच्चतम स्तर पर राजनीतिक जुड़ाव के एक नए मॉडल के रूप में काम किया है। इसलिए दोनों देश अगले दौर की अनौपचारिक शिखर वार्ता भारत में आयोजित करने पर सहमत हुए हैं[32]।

जम्मू और कश्मीर तथा आर्टिकल 370

अगस्त 2019 को भारत ने जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख की प्रशासनिक संरचना में संविधान के माध्यम से कुछ बदलाव किया। इस पर चीन ने अपनी सकारात्मक प्रक्रिया नहीं दी। आरंभ में चीन ने जम्मू कश्मीर के संदर्भ में कहा कि दोनों देशों भारत और पाकिस्तान को संयम रखना चाहिए तथा लद्दाख के मुद्दे पर तीखी प्रक्रिया दी। चीन ने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनने पर अपना विरोध जताया। लेकिन बाद में जम्मू व कश्मीर पर चीन का बदलता हुआ रूप देखा गया। इसका कारण पाकिस्तान से चीन की बढ़ती मित्रता। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन की यात्रा के दौरान चीनी समकक्ष को अपना रूख स्पष्ट किया। विदेश मंत्री ने बताया कि यह भारत का आंतरिक मामला था। उन्होंने आश्वासन दिया कि इससे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा न भारत किसी क्षेत्र पर अपना अतिरिक्त दावा करेगा। इसलिए इस संबंध में चीन की चिंताएं गलत थी। अनुच्छेद 370 पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद चीन ने कहा कि वह लद्दाख को नहीं मान्यता देता, लद्दाख चीन का क्षेत्र है। कोर्ट के फैसले से उनका दृष्टिकोण लद्दाख के प्रति नहीं बदलेगा, वह उसे अपना क्षेत्र मानता रहेगा।

भारत चीन दूसरा अनौपचारिक शिखर सम्मेलन

दूसरे भारत चीन और अनौपचारिक सम्मेलन का आयोजन भारत के चेन्नई शहर में हुआ। इस सम्मेलन में दोनों देशों के नेताओं ने अपने विचार तथा दृष्टिकोण व्यक्त किया कि जिसके द्वारा दोनों देशों के बीच संबंध नई ऊंचाई तक पहुंच सके। दोनों नेताओं ने इस विचार को साझा किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति महत्वपूर्ण पुनर्समायोजन की साक्षी बन रही है। उनका विचार था कि भारत और चीन एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित और समृद्ध दुनिया के लिए काम करने के सामान्य उद्देश्य को साझा करते हैं। जिसमें सभी देश एक नियम–आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के तहत अपने विकास को आगे बढ़ा सकते हैं[33]। उन्होंने अप्रैल 2018 में वुहान, चीन में पहले अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के दौरान इस बात पर बनी सहमति को दोहराया कि भारत और चीन मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में स्थिरता के कारक हैं और दोनों पक्ष अपने मतभेदों का विवेकपूर्ण प्रबंधन करेंगे तथा किसी भी मुद्दे पर मतभेद को विवाद का कारण नहीं बनने देंगे[34]। महान परंपराओं के साथ महत्वपूर्ण समकालीन सभ्यताओं के रूप में, दोनों नेताओं ने दोनों देशों के लोगों के बीच सांस्कृतिक समझ को बढ़ाने के लिए बातचीत को महत्वपूर्ण माना। दोनों नेता इस बात पर भी सहमत हुए कि इतिहास की प्रमुख सभ्यताओं के रूप में, वे दुनिया के अन्य हिस्सों में संस्कृतियों और सभ्यताओं के बीच अधिक संवाद और समझ बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं[35]।दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए की साल 2020 भारत चीन संबंधों के 70 वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी ने भी अनौपचारिक शिखर सम्मेलन को संवाद को प्रगाढ़ बनाने और 'वुहान स्पिरिट' एवं 'चेन्नई कनेक्ट' के अनुरूप नेताओं के स्तर पर आपसी समझ को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण अवसर मानते हुए, इसे सकारात्मक आलोक में देखे जाने की प्रशंसा की। वे भविष्य में इस अभ्यास को जारी रखने के लिए सहमत हुए[36]।

भारत चीन संबंधों को बड़ा आघात तब लगा, जब गलवान में चीन के द्वारा भारतीय सैनिकों पर घात लगाकर हमला किया गया। इसमें दोनों तरफ के सैनिक हताहत हुए। इसमें भारत के कर्नल संतोष बाबू सहित 20 जवान शहीद हुए ।

भारत में जी– 20 सम्मेलन तथा चीन

2023 में भारत में जी–20 सम्मेलन हुआ, जो भारत के बढ़ते प्रभाव का प्रतीक है। इस मंच के माध्यम से भारत ने विश्व को विकास, संरक्षण तथा विश्व कल्याण के लिए अपने दृष्टिकोण के बारे में अवगत कराया। इस सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के स्थान पर लि कियांग ने चीन का प्रतिनिधित्व किया। नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले ही चीन ने भारतीय राष्ट्रपति पद के जी–20 लोगो के नीचे संस्कृत वाक्यांश "वसुधैव कुटुम्बकम्" के उपयोग पर अपनी सहमति व्यक्त नहीं की थी और जुलाई 2023 में आउटकम डॉक्यूमेंट में इस शब्द को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने तर्क दिया कि जी–20 दस्तावेज के आधिकारिक पाठ में "वसुधैव कुटुम्बकम्" शब्द का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि यह संस्कृत में है, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त 6 आधिकारिक भाषाओं में नहीं है[37]। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि "अंग्रेजी में भारत की जी–20 प्रेसीडेंसी का विषय एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है। यह "वसुधैव कुटुम्बकम्" के हमारे सभ्यतागत लोकाचार पर आधारित है, जिसे व्यापक समर्थन मिला है और यह भारत द्वारा जी–20 एजेंडे में लाई गई कई पहलों में शामिल है"[38]। "वसुधैव कुटुम्बकम्" के विरोध करने का यही अर्थ समझ आता है कि वह भारत के बढ़ते 'सॉफ्ट पावर' के प्रभाव से चिंतित है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के संदर्भ में मिली– जुली रणनीति का प्रयोग करते हुए भारत के हितों की रक्षा का यथा संभव प्रयास किया है। उन्होंने सहयोग, संयम, कूटनीति तथा विरोध सब का प्रयोग किया। चीन के साथ लगातार संवादहीनता की स्थितियां कम रही। विभिन्न मंचों पर भारत के पक्ष को तर्क के साथ प्रस्तुत किया। वह पिछले नेताओं के विपरीत, चीन जैसे देश के महत्व और घरेलू वृद्धि और विकास का समर्थन करने के लिए देशों के बीच नाजुक संतुलन बनाए रखने के महत्व को समझते हैं[39]। एशिया विश्व की शक्ति का केंद्र बनेगा इस सपने को साकार करने के लिए आवश्यक है कि भारत –चीन के संबंध अच्छे रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांगरी ला डायलॉग में कहा "मेरा दृढ़ विश्वास है कि जब भारत और चीन विश्वास और भरोसे के साथ एक दूसरे के हितों के प्रति संवेदनशील होकर काम करेंगे तो एशिया और दुनिया का भविष्य बेहतर होगा"[40]।

संदर्भ सूची

1. https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=105940.
2. कुमार, एस. (2014, जुलाई 22). सिगनिफिकेंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंटस विजिट टू चाइना.ICWA. https://icwa.in/show_content.php?lang=2&level=3&ls_id=3078&lid=2381q
3. https://www.thehindu.com/news/National. June 8, 2014.
4. अंकित, पी. (2014, जून 11). चाइना : फॉरेन मिनिस्टरस इंडिया ट्रिप हैस ग्रेट सिगनिफिकेंस. The Diplomat. https://thediplomat.com/2014/06/china-foreign-ministers-india-trip-has-great-significance/
5. वही।
6. वही।
7. वही।
8. https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=106582.
9. https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=106582.
10. https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=109782.
11. https://archive.pib.gov.in/archive2/PrintRelease.aspx?mincode=3.
12. वही।
13. https://www.mea.gov.in/bilateraldocuments.htm?dtl/25240/Joint_Statement_beween_the_India_and_China_during_Prime_Ministers_visit_to_China.
14. वही।
15. वही।
16. वही।
17. कुमार, एस एण्ड रंजन, आर. (2016, जून 3). प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जीस विजिट टू चाइना :मिनिमाइजिंग डिफरेंसस, मैक्सिमाइजिंग कन्वर्जेंस. ICWA. https://www.icwa.in/show_content.php?lang=1&level=3&ls_id=1792&lid=791
18. वही।
19. वही।
20. वही।
21. वही।
22. वही।
23. द्विवेदी, जी. जी. (2017,अगस्त 11). डोकलाम, चाइनास स्ट्रैटेजिक कैलकुलस एण्ड इंडियास पॉलिसी ऑप्शंस. IDSA. https://idsa.in/idsacomments/doklam-china-

strategic-calculus-and-india-policy-options_ggdwivedi_110817
24. कुमार, एस एण्ड राकेश, पी.(2018, मई 24). वुहान समिट. ICWA. https://www.icwa.in/show_content.php?lang=1&level=3&ls_id=2515&lid=1807sss
25. वही।
26. वही।
27. वही।
28. वही।
29. वही।
30. वही।
31. वही।
32. कुमार, एस. (2018,जून 13). फ्रॉम वुहान टू किंगदाओ : एन अपडेट आन रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडिया चाइना टाईस. ICWA. https://www.icwa.in/show_content.php?lang=1&level=3&ls_id=2498&lid=1805
33. https://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/31938/2nd_IndiaChina_Informal_Summit
34. वही।
35. वही।
36. वही।
37. सिंह, टी. (2023,सितंबर 27). चाइना एण्ड द जी –20 समिट 2023. ICWA. https://www.icwa.in/show_content.php?lang=1&level=3&ls_id=9962&lid=6362
38. वही।
39. भट्टाचार्य, जे. (2023, जून). इंडिया –चाइना रिलेशंस अंडर पी एम नरेंद्र मोदीः एन ओवरव्यू, *हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जर्नल, 11*(1), 22.।
40. https://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/25240/Joint_Statement_between_the_India_and_China_during_Prime_Ministers_visit_to_China